राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 38 अंक 2 मई 2015 मूल्य 5 रु. पृष्ठ 32

नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में 'प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद' के तहत राहतकार्य में लगे कार्यकर्ता तथा डाक्टर। इनसेट में जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित करते हुए रा. स्व. संघ के मा. सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले तथा अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर

तिरूवंतपुरम (केरल) में हुए 'जिज्ञासा-2015' के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा तथा मंच पर अन्य अतिथिगण

बेंगलुरु (कर्नाटक) में हुए ‘सृष्टि-2015’ में पुरस्कार प्राप्त छात्रों को सम्मानित करते हुए कर्नाटक के मा. राज्यपाल श्री वजूभाई वाला।
साथ में अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री रविकुमार तथा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री के. एन. रघुनंदन

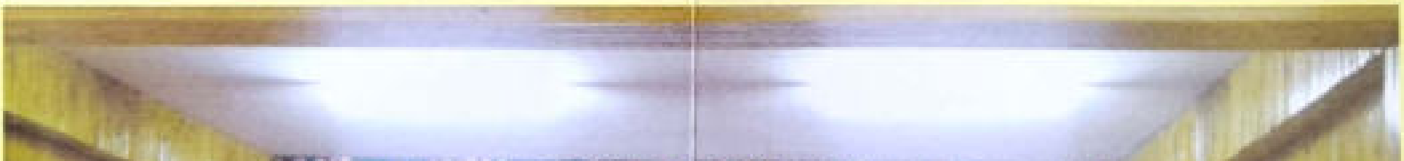

गुवाहाटी में हुए ‘आरोहण-2015’ के उद्घाटन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर का स्वागत करते हुए ।
साथ में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. ओंकार राय

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक मण्डल

आशुतोष

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-23216298

ईमेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com

ब्लॉग :chhatrashaktiabvp.com

वेबसाईट :www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली - 110007 से प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के-30, नवीन शाहदरा, दिल्ली - 110032 द्वारा मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय

"छात्रशक्ति भवन"

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली - 110002

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं.
संपादकीय	4
तिरूवनंतपुरम में आयुर्वेद पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संचन्न	6
शक्ति के रचनात्मक उपयोग से ही राष्ट्र निमार्ण – सुनील आंबेकर	7
नयी शिक्षा नीति – दिशा – प्रो. मिलिंद मराठे	8
नेपाल की तबाही और अभाविप का योगदान	11
हमारी जमीन हिल रही है – अक्षय दुबे	13
जमशेदपुर में प्रदेश छात्रा सम्मेलन संपन्न	15
जम्मू–कश्मीर में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन	17
संवाद से मिटेगा अलगाव – आशुतोष भटनागर	18
मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिला डूसू प्रतिनिधिमंडल	21
सृष्टि – 2015 बेंगलुरू में संपन्न	23
कैरियर – गैर परंपरागत रोजगार के क्षेत्र – मुकेश	24
खतरे में डिजिटल डेमाक्रेसी – अमित चौहान	26
सी–सैट क्वालीफाइंग.....अभाविप का जश्न	27
निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ झारखंड में चक्का जाम	28
प्रतिबंधित हो गौवध और गौमांस – रविशंकर	29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

हिमालय व्यथित है। उसके गर्भ में जहां बहुत कुछ उमड़ रहा है वहीं धरातल पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा जो उसे बेचैन कर रहा है।

भूगर्भीय प्लेटें आपस में टकरा रहीं हैं। धरती कांप उठती है और उसके ऊपर बने भवन ताश के महल की तरह धराशायी हो जाते हैं। समृद्धि के प्रतीक बने ये महल बिखरते हैं और बिखर जाती है जिंदगी भी। शहर तबाह हो जाते हैं और गांव वीरान। जिंदगी भर की जमा–पूंजी पलक झपकते खाक में मिल जाती है। नेपाल में यही हुआ है।

विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है। हिमालय की छाती पर उग आये कंक्रीट के जंगल सांस लेने की जगह तक नहीं छोड़ते। इंट, पत्थर, लोहा और सीमेंट। मंजिल–दर–मंजिल लादते जाते हैं, बिना प्रकृति की संवेदनशीलता को जाने। और जब हिमालय अंगड़ाई लेता है, नदियां करवटें बदलती हैं तो प्रलय के दृश्य आ उपस्थित होते हैं। पिछले साल हमने यह श्रीनगर में देखा, उससे पिछले साल केदारनाथ घाटी में। पीछे छूट जाती हैं वेदना की स्मृतियां, जिनमें से मनुष्य अपनों को खोजता है, पुनः अपने नीड़ का निर्माण करता है, जीवन नये सिरे से अपनेआप को अभिव्यक्त करता है।

इन्हीं में से कुछ घटनाएं होती हैं अविश्वसीय, अकल्पनीय, जिन्हें कुछ लोग चमत्कार की श्रेणी में डाल देते हैं। यह संयोग है कि केदार घाटी में केदारनाथ मंदिर और काठमांडू मे पशुपतिनाथ मंदिर इस दैवी आपदा से अप्रभावित रहे। चमत्कार सिद्धांत से पृथक इसके वैज्ञानिक पक्ष पर भी अध्ययन होना चाहिये। प्रकृति के अनुकूल वास्तुनिर्माण कला प्रकृति को अवकाश देती है और मनुष्य को सुरक्षा। प्रकृति और मानव के सामंजस्य से उत्पन्न जीवनशैली, जिसके कारण भारत की अपनी पहचान बनी, उससे दूर जाने का दंश हम झेल रहे हैं। पश्चिम की दृष्टि से उत्पन्न विकास के अंधेरे पक्ष के भुक्तभोगी हैं हम।

इस अंधेरे के बीच कुछ उजली रेखाएं भी हैं। भोग की दुनियां में विचरण करते हुए इस विश्व में प्राकृतिक आपदा के क्षणों में मानवीय संवेदनाओं के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जन्म लेते हैं। परस्पर अपरिचित लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, अपने कष्ट भूल कर दूसरों को बचाते हैं। सदियों का वैर–भाव क्षण भर में मैत्री में बदल जाता है। ऐसे समय में मैत्री की परीक्षा होती है। जो ऐसे समय में भी राजनीति करते हैं, उनका चरित्र भी जगजाहिर हो जाता है। नेपाल के घटनाक्रम में भी यह सब हुआ है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित देश की तमाम समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी यथासंभव त्वरित सहायता

पहुंचाने का प्रयास किया। दोनों संगठनों के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने स्वयं काठमाण्डू पहुंच कर सहायता कार्य का नेतृत्व संभाला।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे सहायता कार्य का संचालन किया। कुछ घंटों के भीतर ही सहायता पहुंचाने के प्रयास की सर्वत्र सराहना भी हुई। यद्यपि बाद के दिनों में चली अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दांव और भारतीय मीडिया के बड़बोलेपन के चलते कुछ कठिनाइयां भी पैदा हुई किन्तु यह भारत की जिम्मेदारी थी जिसे भारत ने बखूबी निभाया।

मोदी सरकार को इस माह एक वर्ष पूरा हो जायेगा। इस एक वर्ष का स्वाभाविक ही मूल्यांकन होगा। नेपाल की आपदा पर त्वरित प्रतिक्रिया के साथ ही यमन से भारतीय सहित 40 से अधिक देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का श्रेय इस सरकार की उपलब्धियों में से प्रमुख है। अनेक साहसिक निर्णय और खुली सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जहां सरकार के पक्ष में जायेगी वहीं निर्णयों के धीमे क्रियान्वयन पर सवाल भी उठेंगे। नरेन्द्र मोदी ने जहां संगठन में रह कर दशकों तक अपने आप को वर्तमान चुनौतियों के लिये तैयार किया है वहीं उनके सहयोगी भी कम तैयारी के चलते उनके साथ कदम मिला कर चलने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। संभवतः धीमे क्रियान्वय के पीछे यही कठिनाई है।

विपक्ष तो इस परिवर्तन से हतप्रभ है। नयी सरकार ने राजनीति का जो व्याकरण गढ़ा है वह अभी तक की राजनीति से सर्वथा अलग है। मुख्य विपक्षी दल अपनी राजनैतिक जमीन खोने के बाद आन्तरिक संघर्ष से जूझ रहा है। मुद्दाविहीन राजनीति और सनसनी से वंचित मीडिया अंधेरे में लाठी भांजने का करतब दिखा रहे हैं। उम्मीद की किरण की तरह सामने आयी आम आदमी पार्टी की नियति 1977 की जनता पार्टी से अलग नहीं दिख रही। ऐसे में देश के राजनैतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव अवश्यंभावी है। इस परिवर्तन को अंतिम निष्पत्ति तक पहुंचाने में देश के छात्र–युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है जिसके लिये अभाविप निरंतर प्रयासरत है। ■

जिज्ञासा-2015

तिरूवनंतपुरम में आयुर्वेद पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न

'जिज्ञासा' कार्यक्रम में मॉडल का अवलोकन करते केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा

विद्यार्थी सेवा ट्रस्ट तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, केरल इकाई के संयुक्त तत्वावधान में केरल के तिरूवनंतपुरम में आयुर्वेद पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी (8 से 12 अप्रैल 2015) को सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने किया।

वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए विरासत से मिले ज्ञान और आधुनिकता का एक मंच पर समावेशी के रूप में होना, एक बेहतर अनुभव वाला रहा। इस आयोजन का उद्देश्य हर्बल उद्योग का आधुनिक और पारम्पारिक चिकित्सा क्षेत्र का पता लगाना है।

इसमें आधुनिक और परम्परागत दवाओं पर एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य जागरूकता प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन केरल के पर्यटन मंत्री श्री ए. पी. अनिल कुमार ने किया।

'जिज्ञासा 2015' स्वास्थ्य प्रदर्शनी का विषय पारम्पारिक दवाओं के साथ आधुनिक दवाओं के योगदान पर था। यह प्रदर्शनी 'निरामय–रोग मुक्त भारत' इस विषय पर आधारित थी। आयुर्वेद पर जोर डालने के लिए इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का केन्द्रीय विषय 'केरल का आयुर्वेद पर झुकाव' के साथ–साथ 'आयुर्वेद शिक्षा का पुनर्गठन–संभावना और चुनौतियां' था। इस कार्यक्रम के द्वारा देश के विभिन्न कॉलेजों से आये डॉक्टरों और वैद्यों को एक मंच प्रदान किया गया।

आयुर्वेद, सिद्ध, योग आदि से जुड़े एक हजार प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। जिज्ञासा के तहत पांच दिवसीय प्रदर्शनी, परिचर्चा और कार्यशाला में देशभर से आये शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और उद्योगपतियों ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई।

इस संगोष्ठी के अंतिम सत्र को केरल के स्वास्थ्य मंत्री श्री वी. एम. शिवकुम्भ ने संबोधित किया जबकि संगोष्ठी के समापन सत्र को अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने संबोधित किया। ■

आरोहण-2015

शक्ति के रचनात्मक उपयोग से ही राष्ट्र निर्माण - सुनील आंबेकर

नोर्थ ईस्ट क्षेत्र प्राकृतिक विहंगम छटा और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इस क्षेत्र में इतनी काबिलियत है कि देश विकास में न केवल योगदान दे बल्कि उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आजादी के छह दशक बाद भी यह क्षेत्र पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है कि यहां की प्रतिभा को दिखाने का अवसर नहीं मिला। जानकारी के अभाव में क्षेत्र के संभावित प्रतिभा का परिचय देश को हो नहीं पाया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की असम इकाई ने इंजीनियरिंग छात्रों को 'आरोहण' के बैनर तले एक मंच उपलब्ध कराया। राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों ने अपनी सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता का अच्छा प्रस्तुतीकरण आरोहण में किया। यह कार्यक्रम 25 और 26 अप्रैल, 2015 को स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गुवाहटी में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर व सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महा निदेशक डॉ. ओमकार राय ने किया। इस मौके पर अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर और आरोहण 2015 के संयोजक श्री कृष्ण किंकोर महंत मौजूद थे।

उदघाटन सत्र में श्री सुनील आंबेकर ने कहा कि शक्ति का उपयोग सही कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा शक्ति का रचनात्मक उपयोग राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका अदा करता है, शक्ति का गलत इस्तेमाल राष्ट्र के लिए विध्वंसकारी होता है। उन्होंने अभाविप के असम इकाई को आरोहण के आयोजन पर बधाई दी और कहा कि इस तरह के आयोजन से ही क्षेत्र की समस्याओं का निदान और विकास संभव है।

मुख्य अतिथि डॉ. ओमकार राय ने कहा – भविष्य में सूचना तकनीकी में नौकरी के अवसर काफी मिलेंगे। उन्होंनें देश के विकास में डिजीटल इंडिया पर जोर दिया। आरोहण कार्यक्रम में असम के नौ और मेघालय को दो इंजीनियरिंग कॉलेजों से सौ से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया। इसमें 15 अंतिम वर्ष के प्रोजेक्ट और 20 हॉबी / वर्किंग मॉडल के साथ 10 टेक्निकल पेपर प्रजेन्टेशन को शामिल किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहटी से जुड़े प्राध्यापकों को इस कार्यक्रम का जज बनाया गया। 12 सदस्यीय निर्णायक मंडली ने प्रत्येक प्रोजेक्ट को देखा, परखा। आरोहण कार्यक्रम के दूसरे दिन विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इसके समापन सत्र में डोनर (DoNER) मंत्रालय के मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनका स्वागत अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर और आरोहण कार्यक्रम के सहसंयोजक ज्योर्तिमय गोस्वामी ने किया।

केन्द्रीय मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने उपस्थित युवाओं से कहा कि क्षेत्र के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें उभारने और मंच मुहैया कराने की जरूरत है। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए तथा बेहतर रोजगार के लिए यहां से दूर के दूसरे भागों में जाना पड़ता है और उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। दिल्ली में यहां के युवाओं के लिए छात्रावास, काउंसलिंग सेंटर और स्टडी सेंटर दिल्ली समेत नामी विश्वविद्यालयों में स्थापित कर रही है।

अभाविप की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यह संगठन देश का सबसे पुराना और बड़ा छात्र संगठन है। उन्होंने कहा कि श्रीहरि बोरिकर के नेतृत्व में यहां की संस्कृति, शिक्षा और युवाओं की प्रतिभा को मंच मिल रहा है, उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय विद्यार्थियों के रचनात्मक क्रियाकलापों में हर संभव मदद करेगा। ■

नयी शिक्षा नीति - दिशा

✍ प्रो. मिलिंद मराठे

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी गयी थी और 1992 में उसमें संशोधन करते हुए संशोधित राष्ट्रीय नीति बनायी गयी थी। आज लगभग 28 वर्ष बीत गये। शिक्षा की स्थिति में और समाज में कई परिवर्तन आ गये है। समाज में शिक्षा की चाह बढ़ी है। अधिक संख्या में लोग शिक्षा लेने आ रहे है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान इस विषय में आज नागरिकों की आवश्यकताएँ बढ़ी है। यह बदली हुई स्थितियाँ एक नयी शिक्षा नीति साकार करने के लिये दबाव बना रही है। भारत सरकार ने भी इस स्थिति को समझते हुए 'नयी शिक्षा नीति करे साकार, ज्ञान, योग्यता और रोजगार' यह घोष वाक्य अपने संकेत स्थल पर डालकर भारत को ज्ञान–शक्ति के रूप में बनाने की इच्छा व्यक्त की है। छात्रों में ज्ञान, कौशल एवं उचित रवैय्या निर्माण कर भारत की शिक्षा को नयी दिशा देने का संकल्प भारत सरकार ने किया है और नीतिगत परामर्श के लिये नागरिकों को आहवान किया है। अतः अभाविप जैसे संगठनों का यह दायित्व बनता है की नीतिगत सुझाव देने में सहभागी हो।

1.नई शिक्षा नीति का उद्देश्य :– भारतीय विचार एवं तत्वज्ञान के आधार पर ज्ञान संक्रमित करना, कौशल विकास करना एवं सर्वांगिण व्यक्तित्त्व विकास करना जो छात्रों में आत्मविश्वास, आत्म सम्मान, सामाजिक दायित्व का बोध एवं जिम्मेदारी का एहसास, लोकतांत्रिक प्रणाली पर अटूट विश्वास एवं भारतीय परिवार मूल्य एवं नीति मूल्य पर प्रखर विश्वास निर्माण कर सके। शिक्षा प्राप्त छात्र सामाजिक परिवर्तन का वाहक एवं सामाजिक कुरितियों को समाप्त करने वाला सैनिक बन सके ऐसी शिक्षा हमें देनी होगी। उद्योजकता, रचनात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, श्रम के प्रति सम्मान की भावना ऐसे गुणों से युक्त छात्र बने यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये। आजीविका चलाने की क्षमता उत्पन्न होना, संपत्ति निर्माण (Wealth Creation) करने की क्षमता विकसित होना यह तो शिक्षा का उद्देश्य है ही। मगर समन्वयवादी, विभेदों का सम्मान करनेवाला, शुद्ध नैतिक चरित्र वाला सबके प्रति समानता एवं उदारता का भाव रखनेवाला 'वसुधैव कुटंबकम्' की भावना व्यवहार में लाने वाला मानव निर्माण करना शिक्षा नीति का उद्देश्य होना चाहिए।

सकल नामांकन अनुपात (GER- Gross Enrollment Ratio) को 2020 तक 30% तक बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षा का स्वरूप, पद्धति, पाठयक्रम का निर्माण भारतीय हो। आयुर्वेद, योग, मानसशास्त्र, भारतीय भाषाओं को महत्ता मिले। मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता हो। U.G. / P.G. तथा Ph. D. स्तर तक की शिक्षा भारतीय भाषा में उपलब्ध हो।

2.नई शिक्षा नीति Governance (अभिशासन) :– स्वायत्त 'राष्ट्रीय शिक्षा पीठ' की स्थापना हो जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा का एकात्मिक विचार, दिशा निर्देश, क्रियान्विती हो। शिक्षा क्षेत्र के सभी घटकों के अर्थपूर्ण सहभाग से योजना, निर्णय प्रक्रिया और क्रियान्विती हो। पारदर्शिता, सभी नियमों Regulations का कड़ाई से पालन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली एवं जवाबदेही यह Governance के मुख्य सूत्र हो।

भारतीय शिक्षा सेवा (IES - Indian Education Service) का गठन हो और शिक्षा के परिणामकारक, अर्थपूर्ण और संजीदा (Sensible) अभिशासन के लिये अधिकारियों का चयन IES से ही हो। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा किया जाने वाला शैक्षिक गुणवत्ता प्रमाणिकरण सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों को अनिवार्य किया जाये।

भारतीय परिस्थिति के अनुकूल संकेतकों के आधार पर स्वयं अपनी रैंकिंग पद्धति तैयार करनी चाहिये जो विश्व रैंकिंग के साथ मेल खाती हो। हमे कार्यक्रम

प्रत्यायन और संस्था प्रत्यायन दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। प्रत्यायन की प्रकिया को निर्धारित समय में पूरा करने की चुनौती हमारे सम्मुख है। अतः राज्यों के विशेष गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों को अपनी प्रत्यायन युनिट स्थापन करने की अनुमति देकर प्रक्रिया को विकेंद्रित करना चाहिये लेकिन किसी भी हालत में निजी संस्थाओं को प्रत्यायन एजेंसी नहीं बनाना चाहिये। शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। अतः छात्र, अध्यापक, संस्थाचालक एवं सरकारें इनके बीच विवाद भी बढ़ रहे हैं। उन विवादों का समयबद्ध, परिणामकारक और गति से निपटारा होने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर शैक्षिक न्यायाधिकरण (Educational Tribunals) बनाये जाये।

3. **गुणवत्ता** :– सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज की आवश्यकता है। दिसंबर 2011 के आँकड़ों के अनुसार 47 उच्च शिक्षा राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा और कला वाणिज्य इन संकायों में 71.82% शिक्षा होती है। अतः जब हम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते है तो मुख्य रूप से कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों की और राज्य विश्वविद्यालयों के गुणवत्ता के बारे में सोचना अपरिहार्य है। शिक्षकों की बेहद कमी और उनकी तदर्थ नियुक्ति (Ad hoc) यह समाप्त होना चाहिये। राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों में अर्हता प्राप्त शिक्षकों की कमी को तुरंत समाप्त कर नियुक्तियाँ होनी चाहिये। उनकी भर्ती प्रक्रिया अविलंब शुरू होनी चाहिये। सेवा पूर्ण प्रशिक्षण एवं सेवांतर्गत Refresher Course शिक्षकों को अनिवार्य करना चाहिये। प्रयोगशाला, उपकरण, ग्रंथालय, कक्षाएँ एवं अन्य संसाधनों की कमी को दूर करने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों में वित्तिय पुनरूद्धार योजना (Financial Revival Plan) अविलंब लागू हो। पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिये। उद्योगकता, विविध कौशल विकास, Soft Skills विकास ऐसे विषयों को पाठ्यक्रमों में जोड़ना चाहिये। गुणवत्ता की चाह रखने वाले महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करना जिससे वो पाठ्यक्रमों का सृजन कर सके और छात्र/अध्यापक अनुपात 20 से कम रखते हुए CBCS लागू करना उपयोगी होगा।

अनुसंधान को हर संभव प्रोत्साहित करना जरूरी है। शोध प्रकल्पों के लिये निधी आवंटन, शोध पत्र लिखने हेतु प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिये। जो अध्यापक ऐसे विविध गतिविधियाँ करते है उनके लिये Academic Performance Linked Incentive शुरू करना चाहिये।

सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ एवं पाठयेतर गतिविधियाँ छात्रों के व्यक्तित्त्व विकास हेतु आवश्यक है। अतः खेलकूद, संगीत, नाटय, नृत्य, योग ऐसी गतिविधियाँ बढ़ायी जाये। छात्रों के लिये व्यवसाय मार्गदर्शन केन्द्र और कैरियर परामर्श केन्द्र प्रत्येक महाविद्यालय में खोले जाये और वहाँ तज्ञों की नियुक्ति हो। प्रत्येक कक्षा का 90% पाठयक्रम महाविद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य हो।

4. **उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था** :– उच्च शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का न्यूनतम 6% या बजट परिव्यय का 10% आवंटित हो और धीरे धीरे यह बढ़ता जाये। इससे शिक्षा का व्यावसायिकरण बंद होगा और सस्ती शिक्षा सभी को मिलेगी।

Education Development Bank of India (EDBI) की स्थापना हो और उसके द्वारा वित्तीय व्यवस्था हो। महाविद्यालयों को गुणवत्ता सुधार हेतु मदद, गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिये न्यूनतम ब्याज दरों पर शैक्षिक ऋण, छात्रों के लिये छात्रवृत्ति एवं Free Ship, अनुसंधान हेतु राशि ऐसे कई वित्तिय गतिविधियाँ EDBI करें।

शिक्षा का प्रतिवर्ष एक विद्यार्थी पर होने वाला व्यय सरकार तय करें और यह व्यय शिक्षा क्षेत्र का लाभ लेनेवाले सभी घटकों से लिया जाये। संस्था चलाने वालों से Capital Cost, छात्रों से शुल्क, कंपनियों से CSR में खर्च होने वाले राशि का निश्चित प्रतिशत, सरकारों से विविध सुविधाएँ और समाज एवं पूर्व छात्रों से Donations जो आयकर से 100% मुक्त

हो, इस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था सोची जाये।

भारत जैसे विविध आर्थिक स्तर वाले देश में Uniform Fee Structure योग्य नहीं है। उसकी तुलना में Differential Fee Structure उपयोगी है। 40% सीटें बहुत ही कम शुल्क में, 40% सीटें Cost/Student/Year के हिसाब से और 20% सीटें मैनेजमेंट द्वारा 4 गुना शुल्क से भरी जाये।

5. शिक्षा के नये आयाम :– केवल पारंपारिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा की सभी जरूरतों को पूर्ण नहीं कर सकती। Life Long Learning ही किसी भी शिक्षा प्रणाली की बुनियाद है। अतः पारंपारिक शिक्षा के साथ साथ मुक्त एवं दूरस्थ (Open & Distance Learning) शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिये। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री का निर्माण, समयबद्ध, अनुशासनपूर्ण क्रियान्विती, न्यूनतम 15 दिन / 1 माह के Contract hours की अर्थपूर्ण क्रियान्विती, सख्त एवं निष्पक्ष परीक्षा पद्धति ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता एवं विश्वासार्हता को निश्चित करेगी।

Internet, Computer की प्रचूर मात्रा में उपलब्धता के कारण प्रौद्योगिकी–समर्थित शिक्षा का एक नया दालन खुल गया है। Online Education, Web-baned Learning & Certification ये नये विचार है। व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रम (Massive Open Online Courses (MOOCs), NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning), Virtual Class Rooms, Interactive Learning आदि विविध विधाएँ उपयोगी साबित हो रही है। व्यापक पहुँच, शिक्षा की लागत को कम करना, विषयवस्तु का समृद्ध एवं परिणामस्वरूप चित्रण, स्वयं की पढ़ने की गति से मेलजोल और व्यापक जानकारी तक पहुँच यह E-Learning के लाभ है।

अतः प्रौद्योगिकी–समर्थित शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ अनुपूरित (Supplementary) किया जाना चाहिये।

6. विस्तार–उत्कृष्ठता–समता :– यह तीन बिंदू शिक्षा के लिये आवश्यक है। और विनिमयन (Regulation) के मुख्य उद्देश्य है। भारत में शिक्षा का विस्तार विविध क्षेत्रों और समूहों के बीच असमानताओं से भरा है।

प्रादेशिक असमानता, अनुसूचित जाति– जनजाति में GER की कमी, ग्रामीण और शहरी महिलाओं में GER में असमानता है। पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार कम है।

अधिकाधिक छात्रावासों की सुविधा छात्रा एवं जनजाति के लिये बढ़ाना, शिक्षा का भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना ऐसे उपाय समता के नाते करने होंगे। यद्यपि शिक्षा का विस्तार जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी ओर शिक्षित युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार है। आवश्यक कौशल विकास न होने के कारण यह स्थिति आयी है। अतः क्षमताओं के विकास को ध्यान देना पड़ेगा। उद्योगिकीय प्रेरणा, स्वयं रोजगार हेतु छात्र को सक्षम बनाना आवश्यक है। पढ़ाई करते समय छात्र अपने गाँव, समुदाय समाज के कौन सी जरूरतों को पूरा कर सकते है, उनके विकास में क्या योगदान दे सकते है यह सोचना होगा। पर्यावरण संरक्षण, जलसंधारण, मृदासंधारण, उर्जा बचत के प्रयास, पौधरोपण, साक्षरता अभियान, पिछड़े–जनजाति–वर्ग की सेवा, भारतीय भाषा सीखना / सीखाना, स्वास्थ्य जानकारी देना, लसीकरण, टिका लगवाने में सहायता ऐसे विकास के कई कार्य छात्र करें। तीन माह का सामाजिक Intership को U.G / P.G स्तर पर अनिवार्य करना चाहिये।

योग, संस्कृत, आयुर्वेद ऐसे विशेष विषयों पर अभ्यास क्रमों का निर्माण करके इनको विदेशों में चलाना चाहिये। जिन विद्याशाखाओं में भारत की संस्थाए गुणवत्तापूर्ण है उन पाठयक्रमों को दुनियाभर में लागू करने के प्रयास हो। इस प्रकार एक अच्छी शिक्षा नीति हम मिलकर बनाये। ■

नेपाल की तबाही और अभाविप का योगदान

25 अप्रेल, 2015 को दोपहर आये विनाशकारी भूकंप ने नेपाल को तबाह कर दिया। रिक्टर पैमाने पर 7.9 तीव्रता वाले भूकंप का केन्द्र मध्य नेपाल के लमजुड़ में घन नेपाल के समीवर्ती भारतीय जिलों में भी भूकंप से काफी नुकसान पहुंचा। नेपाल के काठमांडु, ललितपुर, भक्तपुर, धादिंड, गोर्खा, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, तनहं, रसुवा समेत 22 जिलों में बड़े पैमाने पर जन–धन की हानि हुई। भूकम्प में अब तक 8000 से अधिक लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। 7000 से ज्यादा घायलों की इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।

काठमांडु, भक्तपुर, धादिड, गोर्खा, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा आदि जिलों में अधिकांश घर पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से लाखों लोग खुले आकाश में रहने की बाध्य हुए। उस पर बारिश ने जीवन और कष्टकर बना दिया। खाद्यान्न, पानी तथा औषधियों के अभाव में पीड़ित लोग मौत से जूझ रहे हैं।

इस भूकम्प से मानवीय क्षति के साथ ही नेपाल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की इमारतें धरहरा पाटन दरबार, बसन्तपुर दरबार बौद्धस्तूप, भक्तपुर दरबार, पशुपति क्षेत्र के विभिन्न मन्दिर, गोखां का गोखा दरबार, चागुनारायण मन्दिर, रानिपोखरी, दरबार हाइस्कूल आदि राष्ट्रीय महत्व की संरचनायें भी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गयी है। इस राष्ट्रीय विपत्ति की घड़ी में मित्रराष्ट्र भारत समेत विभिन्न राष्ट्रों ने नेपाल की घटना को उच्च प्राथमिकता देते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

अभाविप का योगदान

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आम्बेकर प्रत्यक्ष रूप से नेपाल जाकर वहां के क्षतिग्रस्त गांवों जिसमें धादिड, महाकाल, कापले, गोखां, भगतपुर आदि पर जाकर राहत कार्यों में हाथ बंटाया। परिस्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी की शीघ्रता से अधिकतम और सर्वोत्तम सहायता करने का आह्वान किया। उन्होंने नेपाल के छात्र संगठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् के सभी कार्यकर्ताओं की राहत कार्य में सक्रिय रूप से काम करने की सराहना की है। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर भारत के बिहार, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश राज्य के अभाविप के कई कार्यकर्ता नेपाल में राहत कार्य में जुटे हैं।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि नेपाल के विद्यार्थी संगठन प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद को अभाविप मदद कर रही है। अभाविप द्वारा जो मदद (धन और राहत सामग्री) भारत से जमा होगी, वह प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल के माध्यम से चल रहे राहत कार्य में उपयोग में लायी जायेगी। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य में जुटी हुई है। अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक नेपाल में मौजूद थे।

श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि जब तक विनाशकारी भूकंप के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियां सुव्यवस्थित व सुचारू नहीं होगी तब तक प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद की योजना से चलाये जा रहे राहत कार्य में अभाविप सहयोग करती रहेगी। विशेष रूप से तुरंत दवाईयां, कपड़े व खाने का सामान इत्यादि के साथ विद्यार्थी परिषद धन संग्रह द्वारा नेपाल की मदद करेगी।इस कष्टपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण अवस्था में प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल द्वारा विभिन्न प्रकार की राहत सामग्री

राहत एवं बचाव कार्यो का विवरण

- प्रभावित जनता को खाद्य सामग्री उपलब्ध करना।
- बीमार लोगों के जल्द उपचार के लिये औषधि वितरण करना एवं डाक्टरों की टीम को उन तक पहुंचाना।
- विद्यार्थियों के लिए किताबों की व्यवस्था करना।
- पीड़ित परिवारों को जरूरी बर्तन उपलब्ध करना।
- पुनर्वास की व्यवस्था करना।

नेपाल में भूकंप पीड़ित लोगों को राहत सामग्री बांटते अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर

एकत्र कर प्रभावित लोगों में वितरण करने का काम प्रारंभ किया। 300 से ज्यादा परिषद के कार्यकर्ता पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य में लगे हैं।

पड़ोसी देश की राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में सेवाभावी व्यक्ति, सामाजिक संगठन तथा विभिन्न दानदाताओं से सहयोग की अपेक्षा है। सहयोग करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा निम्न सामग्री वितरण हेतु उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. कम्बल, 2. त्रिपाल, 3. फोम गद्दे, 4. गरम कपड़े (स्वेटर, जाकेट, पेन्ट, सर्ट, टीशर्ट, सलवार, कुर्ता, साड़ी आदि), 5. खाना पकाने के आवश्यक बर्तन (बाल्टी, गिलास, जग, प्लेट आदि), 6. किताब, कापी, पैन आदि 7. सोलर लालटेन, टार्च आदि, 8. आवश्यक खाद्य सामग्री (बिस्कुट, दालमोठ, भुजा, चिअरा, चाउचाउ, चावल, दाल, नमक, तेल, मसालें, चीनी, चायपत्तीयां आदि), 9. चप्पल, जूते, गंमबुट, मोजें आदि। 10. प्लास्टिक की रस्सियां एवं प्लास्टिक शीट।

भूकंप पीड़ितों के लिए देशभर में धन संग्रह

गिरिडीह। भूकंप पीड़ितों के सहायतार्थ अभाविप शहरी क्षेत्र में धन संग्रह कर रही है। अभाविप के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य रंजीत कुमार राय ने बताया कि भूकंप पीड़ितों के सहायतार्थ शहरी क्षेत्र में घूम–घूम कर धन अन्य सामग्री इकट्ठा की जा रही है। इकट्ठा की गई सामग्री व धन को नेपाल भारत में भयावह त्रासदी में बेघर हुए लोगों के बीच वितरित की जाएगी। प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि अभाविप दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है।

सुपौल। धन संग्रह के दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर–झंडा लिए आम लोगों से अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की ताकि बेघर परिवार व भूखे–प्यासे लोगों को बचाया जा सके। धन संग्रह पश्चात अभाविप की ओर से एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में अभाविप के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमन कुमार ने कहा कि अभाविप धन संग्रह के माध्यम से आम–आवाम व सामाजिक संगठन से निवेदन करती है कि विपत्ति की इस घड़ी में जिनसे जो सहयोग बन पाए सहयोग दें। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर मंत्री आदित्य कौशिकी ने की।

जबलपुर। अभाविप के कार्यकर्ताओं द्वारा नेपाल में आए भूकम्प के पीड़ितों के लिए सहायता राशि एकत्रित की। परिषद के उपेंद्र धाकड़ एवं मृदुल मिश्रा ने बताया कि नेपाल में भी विद्यार्थी परिषद का काम प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के नाम से चलता है और हमारे वहां के साथियों पर आई विपदा में पूरा देश नेपाल के साथ है। आपदा के लिए एकत्रित राहत को प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के राहत कोष में भेजी जाएगी।

इसी प्रकार देशभर के अभाविप के विभिन्न इकाईयों, द्वारा नेपाल आपदा से प्रभावित लोगों के लिए धन तथा रोजमर्रा की उपर्युक्त चीजों का बड़े पैमाने पर संग्रह किया गया। जिसे नेपाल के सहयोगी संगठन 'प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद' द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किया जायेगा। ■

हमारी जमीन हिल रही है ...

✍ अक्षय दुबे

हम विकास के उस रास्ते पर गतिमान हैं, जहाँ हमारी जमीन हिल रही है। आसमान फट रहा है, सपने समाप्त हो रहे हैं, इतिहास ध्वस्त हो रहा है। यत्र–तत्र बिखरे हुए कुछ अवशेष चीख–चीख कर मानवीय कृत्यों और क्रूरता पर विमर्श करने और सबक लेने के लिए निर्देशित कर रहे हैं, ताकि हम प्रकृति से तारतम्य स्थापित कर सुरक्षित रह सकें। लेकिन हमें क्या? हमको तो विकास के उस पायदान पर चढ़ना है जहाँ विलासिता नग्न नृत्य करती हो। इसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर बाढ़, सूखा, भूकंप आने के बाद जब चारो तरफ त्राहि–त्राहि मचती है, तब हमारे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता ... । ... और अगर कुछ बचता है तो वो आंसू, चीत्कार, दर्द, बेबसी और मौत का तांडव।

नेपाल में आए भूकंप ने हमें फिर एक बार सोचने पर मजबूर किया है। ये जलजला विकास की परिभाषा को बदलने की प्राकृतिक जिद है। दो हठधर्मियों का टकराव भी, जहाँ मानव और प्रकृति एक–दूसरे से कंधा मिलाकर चलने की बजाय अदावत ठान रहे हैं। आखिर बेचारी प्रकृति भी कब तक जुल्मो सितम सहे। कभी–न–कभी मन में विकार उत्पन्न तो होगा ही थप्पड़ के जवाब में एकाध चपत तो वह भी लगा सकती है। ऐसे भी गाली का प्रत्युत्तर सद्भाव के रूप में कब तक मिलता रहेगा?

कुछ लोग कह रहे हैं कि भूकंप तो भूगर्भीय परिघटना है, प्लेटों, दरारों का खेल है...। इसमें मानवों की क्या गलती हो सकती है? बिलकुल इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता मगर हमें यह भी गौर करना चाहिए कि भूकंप पहले भी आते रहे हैं। फिर जानमाल का नुकसान हर बार बढ़ता क्यों जा रहा है?

इस बार भूकंप में 8,000 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। लाखों लोग बेघर होकर अपने सपनों को ढेर होते हुए देख रहे हैं। धरोहरें, इमारतें, मीनारें सब खाकसार होकर यंत्रणा की बानगी पेश कर रहे हैं।

भूकंप प्रभावित क्षेत्र का मुआयना करते अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले व अन्य

7.9 की तीव्रता से आया यह भूकंप इतना ताकतवर था कि एक झटके में इसने धरती की भौगोलिक सरंचना को ही बदलकर रख दिया। नेपाल चार मीटर भारत की ओर खिसक गया और इसके साथ ही पूरे जनजीवन की जमीन भी डगमगा गई।

सनातन संस्कृति में मान्यता है कि मानवों के पापाचार से व्यथित होकर धरती कांपने लगती है और समूचे जीव जगत को इसका ताप सहन करना पड़ता है। कहीं पाप से आशय प्रकृति को अनदेखा कर अंधे विकास के दलदल में फंसना तो नहीं है? हम इंसानों ने प्रकृति से हर कदम पर बैर मोल लिया है, दुराग्रह की तस्वीर तरक्की के आईने में साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम प्रकृति से हरियाली छीनकर खुशहाली की निरर्थक कामना करने में निमग्न हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले एक साल में 122 जलजले आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि नेपाल का यह जलजला धरती के भीतर से एक चेतावनी है। इससे और भी बड़े जलजले आ सकते हैं।

सभी भूकंप अलग–अलग कारणों से आते हैं। भूकम्पों का अपना–अपना मैकेनिजम होता है। धरती के अन्दर चल रही टेक्टोनिक हलचलों के कारण हो सकते हैं। ज्वालामुखियों की गतिविधियों से, भूस्खलनों या नाभिकीय रासायनिक विस्फोटों के कारण से या विशाल भूमिगत गड्ढों में दुर्घटनाओं की वजह से छोटे भूकंप हो सकते हैं। लेकिन हम मानवों के कारनामों की वजह से विनाश लीला की पटकथा का आगाज और अंजाम केदारनाथ और नेपाल जैसी त्रासदियों से होता है। हिमालयी क्षेत्र काफी संवेदनशील होते हैं। यहाँ पेड़ों की कटाई कंक्रीट आदि के कारण खतरा और बढ़ जाता है। इन क्षेत्रों में विकास परंपरागत रूप से करने की जरूरत है। पहले पहाड़ी इलाकों में वहां की प्रकृति के अनुरूप निर्माण कार्य होते थे। लेकिन अब विकास के नाम पर कंक्रीट निर्माण, पेड़ों की कटाई, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। नदियों पर बाँध और पनबिजली परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि होने से भयावहता और अधिक हो गई है क्योंकि इसके निर्माण में बड़े पैमाने पर डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के प्रयोग से पहाड़ों को नुकसान पहुँचता है और आपदा का खतरा बढ़ जाता है। लोग विकास की इमारतों में दबकर अपना दम तोड़ देते हैं।

बहरहाल ऐसे संकट की घडी में हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने मित्र राष्ट्र के आंसू पोछने के लिए हरसंभव कार्य करें, क्योंकि भूकंप के बाद हजारों लोग कालकलवित हो गए। लाखों लोग बेघर हो गए। कितने ही लोग अनाथ होकर जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। भोजन, दवा, आवास जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहे देश को संकटकाल में संबल की अवश्यमेव जरूरत है। भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पतंजलि योगपीठ द्वारा हरसंभव सहयोग का कार्य किया जा रहा है जो प्रशंसनीय है। अब हमें सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति के हिसाब से ही तरक्की का रास्ता अपनाना पड़ेगा वर्ना विनाशलीला देखने के लिए तैयार रहना होगा। ■

जमशेदपुर में प्रदेश छात्रा सम्मेलन संपन्न

झारखंड के प्रदेश छात्रा सम्मेलन के मंच पर (बाएं से) राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री पुष्कर बाला, कार्यक्रम की उद्घाटक तथा बिहार विधान परिषद सदस्या डा. किरण घई, अभाविप की अ. भा. छात्रा प्रमुख सुश्री ममता यादव। दाएं के चित्र में सुश्री ममता यादव को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित करते हुए

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् झारखण्ड प्रदेश द्वारा "प्रदेश छात्रा सम्मेलन" 2 मई को सूर्य मन्दिर टाउन हॉल, जमशेदपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय 'महिला शिक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण' था।

प्रदेश छात्रा सम्मेलन तीन सत्रों में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विधिवत् उद्घाटन प्रख्यात शिक्षाविद एवं बिहार विधान परिषद की माननीय सदस्य डॉ. किरण घई, अभाविप की अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख सुश्री ममता यादव, विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही तथा दुनिया के सातों महादेशों के सबसे ऊँचे शिखर पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने वाली महिला श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. पुष्कर बाला, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, प्रदेश मंत्री राजेश साह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित किया।

प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि डॉ. किरण घई ने कहा कि हम केवल व्यक्ति नहीं अपितु भारत है, आज इसे जगाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा युवतियां जागृत होंगी तभी तो देश जागरूक होगा और इस युवती जागरूकता अभियान को अभाविप छात्रा सम्मेलन के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के लिए लंबी लकीर खीच दी है।

द्वितीय सत्र में महिला शिक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर प्रस्ताव लाया गया। तृतीय सत्र समारोप सत्र रहा जिसमें विशेष रूप से झारखण्ड सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. नीरा यादव एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सरयू राय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री (अभाविप) श्री गोपाल शर्मा, झारखंड के प्रांत प्रमुख डॉ. श्रवण कु. सिंह अभाविप के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य श्री अमिताभ सेनापति कार्यक्रम के व्यवस्था प्रमुख डॉ. कमलेश कु. कुमलेन्दु उपस्थित थे।

विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल ने कहा कि लक्ष्य और अपने आपका विश्वास किया जाय तो दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। नारी को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से नैतिक रूप से छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा एवं छात्रा समाज निर्माण में अपनी भूमिका के लिए तत्पर रहेंगी। कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराते हुए डॉ. पुष्कर वाला ने कहा कि विद्यार्थी परिषद राज्य में महिला शिक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है और राज्य में व्यापक जागरूकता एवं लोगों की मानसिकता में बदलाव के

लिए जन जागृति लाने में सम्मेलन की भूमिका महत्वपूर्ण है।

दूसरे सत्र में प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव को छात्राओं के समक्ष प्रदेश सह छात्रा प्रमुख सुश्री कृष्णा क्रांति एवं मोनिका कुमारी ने किया।

प्रस्ताव की मुख्य मांगें

1. प्रत्येक प्रखण्ड में कन्या उच्च विद्यालय व प्रत्येक जिला में महिला कॉलेज खोला जाए।

2. छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेजों के पास महिला थाना की स्थापना हो।

3. छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिला में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हो।

4. प्रत्येक जिला में छात्राओं के लिए खेल प्राधिकरण की स्थापना हो।

5. पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक छात्राओं को निःशुल्क और निजी स्कूल कॉलेजों में कम खर्च शिक्षा उपलब्ध करायी जाय।

6. प्रसार माध्यम में विज्ञापनों में महिलाओं का अश्लील चित्रण बंद करने के लिए कानून बनाया जाय।

समापन सत्र में संबोधित करते हुए झारखंड की मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. नीरा यादव ने कहा कि शिक्षा समाज का दर्पण होता है। शिक्षित समाज सभ्य व अनुशासित होता है लेकिन मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं खामियां है। अभिभावकों से लेकर शिक्षक व बच्चों तक का ध्यान परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल करने पर होता है। आज बच्चों को डिग्रिया मिल रही है, लेकिन नैतिकता के अभाव में चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है। अतः प्राथमिक विद्यालयों से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की जरूरत है। डॉ. नीरा यादव ने कहा कि सभ्य व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अभिभावकों व छात्राओं को मानसिकता बदलने, पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से बचने, नैतिकता को अपनाने व बच्चों को भी इसका पाठ पढ़ाने की सीख दी। मंत्री ने सम्मेलन के विषय पर बोलते हुए कहा कि 'नारी शिक्षा, सुरक्षा व सशक्तीकरण तभी संभव है, जब समाज शिक्षित होगा। छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि नारी दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती का रूप है। खुद को कमजोर नहीं समझें, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें, अपने अधिकारों को जाने व कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाएं।

अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गोपाल जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के मूल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई भी देश तभी विकास कर सकता है जब उसकी संस्कृति सुरक्षित रहे और इस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने में महिलाओं की महती भूमिका होती है। भारत तभी विश्वगुरू बन सकता है जब यहाँ की महिलायें शिक्षित सुरक्षित एवं सशक्त बनें।

इससे पूर्व कार्यक्रम में जन्मजात निशक्त एवं जन्म से ही माता–पिता द्वारा परित्यागी गई, छात्रा तथा ट्यूशन पढ़ाकर खुद अपने बलबूते शिक्षा ग्रहण करने वाली जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज की BC A- 2 की छात्रा मिनी पाण्डेय को उनके इस संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा के लिए अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। उनके जीवन के उपर 'I Can Fly' नामक डॉक्यूमेन्टरी फिल्म बनाई गई है जिसकी पटकथा स्वयं मिनी पाण्डेय ने लिखी है।

इस कार्यक्रम का संचालन सुश्री अनामिका शर्मा एवं गौरी साहू ने सयुक्त रूप से किया। ■

जम्मू-काश्मीर में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन

कार्यक्रम में संबोधित करते अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के जम्मू–कश्मीर प्रदेश कार्यालय का उदघाटन 10 अप्रैल, 2015 को अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर द्वारा किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू–कश्मीर प्रदेश संघचालक व अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिग्रेडियर श्री सुचेत सिंह मौजूद थे।

उदघाटन के मौके पर श्री सुनील आंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अ. भा. वि. प. की स्थापना 9 जुलाई, 1949 को हुई थी। जिसका उदेश्य राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए छात्र हित तथा छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना है। अभाविप जम्मू–कश्मीर इकाई को कार्यालय उदघाटन पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यालय का लाभ जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को निश्चित तौर पर होगा।

उन्होंने बताया कि स्टूडेंट नेशनल एसोसिएशन (एसएनए) 1953–54 में अभाविप में सम्मिलित हुआ। तब से जम्मू–कश्मीर में विद्यार्थी परिषद् काम कर रही है। अभाविप ने जम्मू–कश्मीर में कई मुद्दों पर आंदोलन किया। 1990 में 'कश्मीर चलो' आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में पूरे देशभर से करीब दस हजार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ऐसे ही गलत तरीके से मेडिकल कालेजों में नामांकन को लेकर 56 दिनों तक लगातार अभाविप ने आंदोलन चलाया। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में जम्मू और लद्दाख क्षेत्र के साथ भेदभाव को लेकर भी अभाविप ने आंदोलन चलाया है। इस प्रदेश कार्यालय के उदघाटन मौके पर अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. नरेन्दर सिंह ने कहा कि अब तक विद्यार्थी परिषद् का कार्यालय परेड ग्राउंड, जम्मू हुआ करता था। वहीं से सारे कामों का संचालन होता था। अब वेद मंदिर काम्पलैक्स, अम्बफला में विशाल कार्यालय खुलने का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा।

कार्यालय के उदघाटन के मौके पर उत्तर क्षेत्र के प्रचारक श्री प्रेम कुमार, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेन्द्र पांडे, प्रांत प्रचारक श्री रमेश पप्पा, प्रांत कार्यवाह श्री पुरूषोत्तम दधीची, अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री श्रीनिवास, प्रदेश के वन एवं सामाजिक कल्याण मंत्री श्री बाली भगत, प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी समेत सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी परिषद् के पूर्व व वर्तमान कार्यकर्ता मौजूद थे।

कार्यक्रम का संचालन अभाविप के प्रदेश अध्यक्ष डा. विरेन्दर कौडल ने किया जबकि प्रदेश सचिव राहुल देव शर्मा ने कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। ■

संवाद से मिटेगा अलगाव

आशुतोष भटनागर

काश्मीर में अलगाववाद के उद्योग में लगे लोगों ने तिल का ताड़ बनाने में महारत हासिल कर ली है। विडंबना यह है कि उनके इस उद्यम में महज अलगाववादी ही नहीं बल्कि विभिन्न स्थानीय राजनैतिक दल भी शामिल हो जाते हैं जो स्थिति की जटिलता को बढ़ाते हैं। जब कथित राष्ट्रीय मीडिया भी इसमें जानते हुए या अनजाने जुड़ जाता है तो विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय राजनैतिक दल अपने राजनैतिक विरोधी को कठिनाई में देखने का सुख लेने के लिये जब चुप्पी साध लेते हैं तो व्यावहारिक रूप से वे पाकिस्तान प्रेरित अलगाव और आतंक का समर्थन कर रहे होते हैं।

मीडिया का एक वर्ग इन घटनाओं का विष्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि राज्य की गठबंधन सरकार के दो माह के कार्यकाल में स्थितियां दो दशक पीछे की ओर जाती दिख रही हैं। वह इससे दुख नहीं बल्कि एक विशेष संतोष का अनुभव कर रहा है कि गठबंधन के आकार लेते समय की गयी उनकी भविष्यवाणी सही होती दिख रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे गहरी निराशा होगी किन्तु लगता है कि यही उसकी नियति है।

भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में वह पड़ाव आना अभी बाकी है जब परस्पर विरोधी राजनैतिक दल अपने निजी हितों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे। जब तक यह स्थित नहीं आती, जम्मू काश्मीर सहित अनेक राष्ट्रीय प्रश्नों के उत्तर की खोज जटिल बनी रहेगी। आवश्यक नहीं कि यह जटिलता पैरों की बेड़ियां बन अनंतकाल कर विकास के मार्ग को बाधित करे। अधिक संभावना इस बात की है कि यह जटिलता ही वैकल्पिक मार्ग की खोज की ओर प्रवृत्त करेगी और इतिहास का चक्र पूरा होगा।

जम्मू काश्मीर में भाजपा और पीडीपी का गठबंधन कोई अराजक संयोग नहीं है। यह सुविचारित प्रयास है जो समय लेगा, लेकिन निश्चित और सकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन इसके लिये राष्ट्रवादी शक्तियों को सक्रिय समर्थन देना होगा और घाटी में दशकों से जारी झूठ के कारोबार पर निर्णायक प्रहार करना होगा।

प्रश्न उठता है कि आधा मीटर चौड़ी और एक मीटर लंबी जगह में क्या कोई जीवन बिता सकता है। 50 एकड़ भूमि को अगर 4 लाख विस्थापितों में बांटें तो यही क्षेत्रफल आता है। नाजियों के गैस चौम्बर में भी इससे ज्यादा जगह थी। लेकिन यह वही आकार है जिसे लेकर काश्मीर घाटी के अलगाववादी पिछले एक महीने तक आसमान सर पर उठाये रहे।

भारत सरकार ने काश्मीरी हिंदुओं के लिये कुछ आवास बनाने के लिये राज्य सरकार से भूमि खोजने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने इसके हेतु आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की। इस उद्देश्य के लिये 50 एकड़ भूमि की खोज की जानी थी। जानकारी हो कि जम्मू–काश्मीर में प्रस्तावित आईआईटी और आईआईएम के लिये अभी भूमि नहीं खोजी जा सकी है क्योंकि मानक के अनुसार 200 एकड़ से कम भूमि पर इस स्तर का कोई संस्थान नहीं बन सकता। लेकिन कश्मीरी अलगाववादियों ने भ्रम फैलाया कि भूमि के उस 50 एकड़ के टुकड़े पर, जिसकी अभी तलाश भी शुरू नहीं हुई, केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर 4 लाख विस्थापित काश्मीरी हिन्दुओं को बसाने का षड्यंत्र कर रही हैं।

इससे विचलित नौ सांसदों ने एक साथ संसद में सवाल के माध्यम से जानना चाहा कि क्या काश्मीरी पंडितों के लिये किसी विशेष जोन के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। जवाब में गृह राज्य मंत्री हरी भाई पार्थी भाई चौधरी ने सदन को बताया कि विशिष्ट जोन के निर्माण का, विशेषकर जम्मू–काश्मीर के विस्थापित काश्मीरी पंडितों के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। झूठ के

पर्दाफाश की नौबत आने पर इन अलगाववादियो ने घोषणा कर दी कि इस मुद्दे पर केन्द्र व राज्य सरकार ने घुटने टेक दिये हैं और यह उनकी बड़ी जीत है।

हुर्रियत के चेयरमैन गिलानी ने कहा कि नयी दिल्ली ने काश्मीर में काश्मीरी पंडितों के लिये अलग से एक कॉलोनी बसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। राज्य सरकार ने भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं, लेकिन काश्मीर के लोगों ने जिस तरह एक होकर विरोध किया, उससे नयी दिल्ली डर गयी। यह काश्मीरियों की जीत है। कथित उदारवादी मीरवाइज उमर फारुख ने कहा कि नयी दिल्ली को आखिर काश्मीरियों के आगे झुकना पड़ा जेकेएलएफ चेयरमैन यासीन मलिक ने कहा कि यह कॉलोनी अगर बनती तो काश्मीर में इजराइल और फिलिस्तीन जैसे हालात पैदा हो जाते। नयी दिल्ली ने इस कॉलोनी की साजिश हमारी आजादी की मांग को दबाने और काश्मीर के बहुसंख्यक चरित्र को बदलने के लिये रची थी लेकिन काश्मीरी अवाम ने इस साजिश को नाकाम बना दिया है।

मीडिया कई दिन तक पूछता रहा क्या काश्मीरी हिन्दू वापस जाने के लिये तैयार है। लोग तरह–तरह से उत्तर देते रहे और भ्रम की स्थिति बनी रही। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि 50 एकड़ के भूखण्ड पर कितने हिन्दू बसाये जा सकते हैं। क्या कथित काश्मीरियत इतनी नाजुक है कि कुछ सौ हिन्दुओं के आ बसने की आहट से ही उसकी जमीन दरकने लगती है। हर शहर में नये मुहल्ले बसते हैं। इनमें नये लोग आकर बसते हैं। पर इससे सैकड़ों साल पुराने शहर कांपने लगें, यह ताज्जुब की बात है। शायद गिलानी, मीरवाइज और यासीन भूल गये हैं, या भूल जाना चाहते हैं कि जिस श्रीनगर की बात वह कर रहे हैं उसे भी किसी काश्मीरी ने नहीं बल्कि मगध सम्राट अशोक ने बसाया था और गिलानी और उन जैसे अनेक अलगाववादियों के पुरखे बाहर से आकर ही घाटी में बसे थे।

इससे पहले मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद द्वारा दर्शाई गयी सदभावना को धता बताते हुए जेल से हाल ही में रिहा किये गये अलगाववादी मसर्रत आलम ने गिलानी की काश्मीर वापसी पर उनका स्वागत पाकिस्तानी झण्डे लहरा कर किया। मजबूरन मसर्रत को फिर से सलाखों के पीछे भेजना पड़ा। कुछ ही दिन बाद त्राल में आयोजित गिलानी की सभा में भी पाकिस्तानी झण्डे लहराये गये। मुफ्ती ने कड़े कदम उठाने का संदेश देने के लिये गुजरात की धरती को चुना जहां वे पर्यटन को आकर्षित करने के लिये गये थे।

दुर्भाग्य से बढ़ा–चढ़ा कर पेश किये गये विरोध के इस वितान के अंदर हुर्रियत की भीतरी अतर्कलह को देख पाने में सामान्य लोग ही नहीं बल्कि मीडिया के धुरंधर भी नाकाम रहे हैं। छीजते स्थानीय समर्थन के कारण वे लोग बेचैन हैं जिनकी रोजी–रोटी आतंकवाद और अलगाववाद के भरोसे चलती है।

यह भारतीय लोकतंत्र का सौन्दर्य है कि वैचारिक रूप से विपरीत ध्रुव पर अवस्थित राजनैतिक दलों, भाजपा और पीडीपी ने जनाकांक्षाओं का आदर करते हुए सरकार का गठन किया। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में सायास गढ़ा गया अलगाववादप्रेरित और तुष्टिकरणपोषित राजनैतिक ढांचा ध्वस्त हो गया। चकित राजनैतिक पंडितों ने इसे जनाकांक्षा का आदर मानने के बजाय सत्ता की लिप्सा के रूप में निरूपित किया।

जम्मू–काश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफल हो, यह पाकिस्तान के लिये चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। उसकी उंगलियां हरकत में आयीं और घाटी में बैठी उसकी कठपुतलियां नृत्य करने लगीं। अलगाववादी कोरस शुरू हो गया। दुर्भाग्य से पाकिस्तान प्रेरित इस कोरस का विरोध करने के बजाय स्थानीय राजनैतिक दलों ने भी उसमें अपनी तान मिलानी शुरू कर दी।

राज्य विधानसभा में निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद के बयान को पढ़ कर महाभारत के एक पात्र का स्मरण हो उठता है जिसमें उन्होंने मुफ्ती से स्पष्ट घोषणा करने की मांग की है कि इस टाउनशिप के लिये न तो अभी और न ही भविष्य में भी एक इंच भूमि भी नहीं दी जायेगी। एक अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्र ने इस बयान को प्रमुखता से छापा है।

यह सब कुछ दिनों तक चलने वाला ही है क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं, भारत की सरकार ने भी जिस अलगाववाद को खाद–पानी देकर जिस विषबेल को बढ़ाया है उसे जड़–मूल से नष्ट करना होगा। यह दुर्भाग्य ही है कि न तो केन्द्र की सरकार ने और न ही कथित राष्ट्रीय मीडिया ने कभी राज्य में मौजूद राष्ट्रवादी तत्वों को सामने लाने की कोशिश की। चैनलों पर केवल उन्हीं के चेहरे दिखाई देते हैं जो राज्य की विशेष स्थिति का उल्लेख करते हैं या भारत में राज्य के विलय पर प्रश्न उठाते हैं। सरकार और उनके वार्ताकार भी उन्हीं से बात करने में रुचि लेते हैं जो आए–दिन देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं।

इस जड़ तंत्र के भीतर रह कर परिवर्तन का प्रयास निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। अपने अतीत से अलग पीडीपी ने इस गठबंधन में शामिल होने का जो साहस दिखाया है वह भी अभूतपूर्व है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें असफल होने का विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। इसलिये इस प्रयोग के सफल होने के लिये केवल राज्य के कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि देश के सम्पूर्ण राष्ट्रवादी समाज को आगे आना होगा। इसके लिये धैर्य भी चाहिये और रणनीति भी। और इस प्रक्रिया की उद्देश्यपरकता पर दृढ़ विश्वास तो पहली शर्त है ही।

एक और महत्वपूर्ण बिन्दु, अलगाव मिट सकता है अगर संवाद उससे अधिक प्रभावी हो। इसलिये जम्मू–काश्मीर के समाज को शेष देश से काट कर रखने की जो साजिश चली आ रही है उसे तोड़ने का एकमात्र उपाय है हम कही–सुनी बातों पर विश्वास करने के बजाय स्वयं वहां जाकर अनुभव करें, वहां के समाज के साथ संवाद स्थापित करें। दूरियों और दीवारों को मिटाया जा सकता है अगर वहां के लोगों, वहां के तीर्थों, वहां की नदियों, वहां के सांस्कृतिक प्रतीकों और वहां के दर्शन को पुनः चर्चा में लाया जा सके। हजारों वर्ष के सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ कर साठ साल में पनपे अलगाव को समाप्त किया जा सकता है। स्मरण रहे, इस सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने के लिये हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिये हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है। ■

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का मई 2015 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई–मेल पर अवश्य भेजें।

''छात्रशक्ति भवन''
26, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली – 110002
फोन : 011–23216298
ई–मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाईट : www.abvp.org

मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिला डूसू प्रतिनिधिमंडल

दिल्ली प्रदेश मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से वार्तालाप करते अभाविप के दिल्ली प्रदेश मंत्री श्री साकेत बहुगुणा। उनके साथ डूसू अध्यक्ष मोहित नागर, सचिव कनिका शेखावत व अन्य

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार 8 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल से मिला और दिल्ली के सभी विद्यार्थियों की और विशेषतः दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रतिनिधि मंडल में एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा, डूसू अध्यक्ष मोहित नगर, उपाध्यक्ष प्रवेश मलिक, सचिव कनिका शेखावत, सह–सचिव आशुतोष माथुर, एबीवीपी प्रदेश सह–मंत्री सतेंदर अवाना और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका छाबड़ी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने एबीवीपी और डूसू की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और इन समस्याओं के निराकरण हेतु तुरंत कार्यवाही करने की मांग की।

मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल के सामने निम्न मांगों को उठाया गया :–

1. पिछले १७ सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है किन्तु सीटें जस की तस हैं। दिल्ली सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय में नए कॉलेज खोलने चाहिए खासकर दिल्ली देहात के सुदूर इलाकों में जहाँ आज भी कॉलेज की संख्या नगण्य है।

2. देश भर से दिल्ली पढ़ने आने वाले लाखों छात्रों का मकान मालिकों द्वारा अत्यधिक किराया वसूल कर शोषण होता है. दिल्ली सरकार को तुरंत "रूम रेंट कण्ट्रोल एक्ट" दिल्ली में क्रियान्वित करना चाहिए।

3. दिल्ली भर में यूनिवर्सिटी–स्पेशल (यू–स्पेशल) बसों की अत्यधिक कमी है जिससे आम छात्र बहुत परेशान है. दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली के सभी इलाकों से व एनसीआर से तुरंत नयी यू–स्पेशल बसें चलानी चाहिए. साउथ कैंपस में डीटीसी की एक भी बस नहीं चलती है. इस रूट पर तुरंत शटल बस चलनी चाहिए।

4. दिल्ली सरकार के आर्थिक अनुदान से चलने वाले कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं की बुरी स्थिति है. दिल्ली सरकार को उनमें पीने का पानी, कक्षाओं की संख्या, लाइब्रेरी, लैब और खेल सुविधाओं को सुधारने हेतु कदम उठाने चाहिए।

5. SOL के विद्यार्थियों के लिए 'आल–रूट बस पास' की सुविधा मिलनी चाहिए।

6. डीटीसी के बस–पास वातानिकूलित (एसी) बसों में भी मान्य होने चाहिए क्यूंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी दिन में कॉलेज आते जाते हैं जब भीषण गर्मी होती है.

7. दिल्ली मेट्रो में विशेष रियायती पास की सुविधा छात्रों को मिलनी चाहिए। इस हेतु दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए।

8. डीयू के उत्तरी परिसर को एक "कॉम्पैक्ट कैंपस" बनाया जाना चाहिए ताकि छात्राएं यहाँ अधिक सुरक्षित महसूस करें. साथ ही कैंपस में दिन प्रतिदिन बढ़ रही घटनाओं पर भी रोक लगायी जा सके।

श्री केजरीवाल ने एबीवीपी और डूसू पदाधिकारियों से इन सभी समस्याओं को सुना और चर्चा की. उन्होंने तीन मुद्दों पर सिद्धान्तः तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा की वो डीटीसी द्वारा नयी यू–स्पेशल बसें चलवाएंगे. इसके लिए उन्होंने एबीवीपी पदाधिकारियों से बस रूट की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने दिल्ली सरकार के कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं के सुधार का आश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने एबीवीपी और डूसू की कॉम्पैक्ट कैंपस की डिमांड का समर्थन करते हुए इस पर भी काम करने का आश्वासन दिया. इस हेतु भी उन्होंने छात्र–नेताओं से पूरी सूची उपलब्ध करवाने को कहा. बाकी मुद्दों पर भी उन्होंने उचित स्तर पर चर्चा करके उनका निराकरण का आश्वासन दिया।

मीटिंग के बाद एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा ने कहा कि केजरीवाल जी के साथ मीटिंग अच्छी रही और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना. उन्होंने नयी यू–स्पेशल बस चलवाने, कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं के सुधार व कॉम्पैक्ट कैंपस की मांगों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया. हम आशा करते हैं कि वो डीयू के छात्रों की इन बड़ी समस्याओं पर कार्यवाही करेंगे। ■

अभाविप
का मोबाइल ऐप
डाउनलोड
करने की लिंक आपको
ABVP के
अधिकारिक अकाउंट
http://www.facebook.com/ABVPVOICE
https://twitter.com/abvpcentral
पर और वेबसाइट
www.abvp.org
पर भी
उपलब्ध रहेगी।

तकनीकी छात्रों की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता व प्रदर्शन

'सृष्टि-2015' बेंगलुरू में संपन्न

110 इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों द्वारा बनाए गए 208 प्रोजेक्ट का हुआ प्रदर्शन

बेंगलुरु, 3 मई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर्नाटक इकाई की ओर से तकनीकी छात्रों के लिए राज्यस्तरीय प्रतियोगिता-सह-प्रदर्शनी "सृष्टि-2015" न्यू होरिजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलुरु में आयोजित किया गया. 1 से लेकर 3 मई तक आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यभर के 110 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 1570 छात्र, 450 छात्राएं व 103 प्राध्यापकों ने भाग लिया. इंजीनियरिंग के विभिन्न संकायों के छात्रों द्वारा बनाए गए 208 प्रोजेक्ट का प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिनमें कृषि कार्य, कूड़ा निस्तारण, ग्रामीण विकास, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक आपदा से निपटने से संबंधित तकनीकी यंत्र शामिल रहे. इसके अलावा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस समेत 15 विभागों से 159 शोध पत्र भी कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में प्रस्तुत किए गए। प्रोजेक्ट और शोध पत्रों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान तथा बंगलुरु के प्रतिष्ठित कॉलेजों से 80 अनुभवी प्राध्यापकों ने अपना योगदान दिया।

इससे पहले कार्यक्रम का उदघाटन भारी उद्योग मंत्री श्री जी एम सिद्धेश्वर व सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. ओंकार राय ने किया. वही समापन समारोह के मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल श्री वजुभाई वाला थे. समापन समारोह में राज्यभर से आए प्रतिनिधियों से सरल जीवन को अपनाकर श्रेष्ठ विचारों के द्वारा भारत को वैश्विक गुरु बनाने हेतु अपना योगदान देने का आह्वान करते हुए श्री वाला ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ व यश की चिंता छोड़ कठिन परिश्रम व एकाग्रता से निष्ठापूर्वक अपने-अपने क्षेत्र में अगर हम कार्य करेंगे तभी भारत प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। यह आयोजन इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। विद्यार्थी परिषद को देशभक्ति की पाठशाला बताते हुए श्री वाला ने कहा कि परिषद छात्रों में सामाजिक चिंतन का संस्कार प्रवाहित करने का अभिनंदनीय कार्य कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से नशामुक्त भारत बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया।

समापन समारोह में निर्णायकमंडली द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों के प्रतिभागियों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी देखने उद्योगपति, शिक्षाविद, अनुसंधानकर्ता सहित हजारों छात्र आए और आयोजन की सोच व प्रदर्शनी में शामिल छात्रों की रचनात्मकता की सराहना की। ■

कैरियर गैर परंपरागत रोजगार के क्षेत्र

क). योग थेरेपिस्ट

नवीनतम प्रौद्योगिकी ने जीवन को अत्यंत सुगम बना दिया है. इससे शारीरिक श्रम में कमी आयी है. बदलती जीवनशैली में शरीर को चुस्त–दुरूस्त रखने के लिये लोग नये–नये तरीकों की तलाश रहे है. ऐसे समय में योग तेजी से उभरती हुई अपार सम्भावनाओं से भरी विधा है. देश ही नहीं विदेशों में योग के उच्च प्रशिक्षित पेशेवरों की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है.

पाठ्यक्रम : योग में प्रशिक्षण पाने के लिये योग थेरेपिस्ट का पाठ्यक्रम किया जा सकता है. यह पाठ्यक्रम देश के चुनिंदा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलायी जा रही है.

संस्थान : देश के प्रतिष्ठित संस्थान इग्नू में योग के प्रशिक्षण के लिये योग थेरेपिस्ट का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू है. छह माह की इंटर्नशिप सहित इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम की कुल अवधि डेढ़ वर्ष की है. इसके अलावा योग के पाठ्यक्रम यहाँ भी चलाये जाते हैं–

- डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय
- अमरावती विश्वविद्यालय
- गुजरात विद्यापीठ
- गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
- मुम्बई विश्वविद्यालय
- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

अवसर : इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद योग थेरेपी केंद्र खोले जा सकते हैं. विदेशों में योग प्रशिक्षकों की भारी माँग है।

ख). सामाजिक सेवा

सामाजिक सेवा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है. यह एक क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले युवा के व्यवहार कौशल में निरंतर निखार आता है. आजकल युवाओं के बीच यह लोकप्रिय होता जा रहा है. सामाजिक सेवा के जरिये इस क्षेत्र में काम करने वाले को सीधे–सीधे साज के लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है. इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों में स्वतः नेतृत्व के गुणों का विकास होता है।

पाठ्यक्रम : इस क्षेत्र का दायरा बड़ा होने के कारण इससे संबंधित पाठ्यक्रम कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चलाये जा रहे हैं। समाज सेवा में डिप्लोमा, डिग्री व स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम अनेक विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं।

संस्थान

- दिल्ली विश्वविद्यालय
- जामिया मिलिया इस्लामिया
- टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस

अवसर : सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्रों विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों में ऐसे युवाओं की भारी माँग है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे।

ग). ग्रामीण विकास

इस पाठ्यक्रम के तहत गाँवों में बसने वाले लोगों के समग्र विकास का अध्ययन आता है. इसमें मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. तेजी से परिवर्तनशील ग्रामीण व्यवस्था में सुधारके लिये सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा गाँवों में रहने वाले लोगों के विकास में खर्च करती हैं. ग्रामीण विकास को करियर के रूप में इसलिए भी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि यह एक व्यापक क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

पाठ्यक्रम : रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करने के लिए 12वीं के बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क करके सीधे फील्ड में काम कर अनुभव पा सकते हैं या फिर इसके उपरांत दो साल का मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स करके कैंपस प्लेसमेंट से जॉब हासिल का सकते हैं. रिसर्च क्षेत्र में जाने के लिए दो वर्ष का एमफिल भी कर सकते हैं. आगे आप चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं।

संस्थान
- दिल्ली विश्वविद्यालय
- इग्नू
- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
- जामिया मिलिया इस्लामिया
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट

अवसर : इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद रोजगार की संभावनायें बढ़ जाती है. केंद्र व राज्य सरकार के विभागों अथवा संसाधन केंद्रों के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर की सामाजिक विकास ईकाईयों, दान देने वाली राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जा सकता है. ये रोजगार प्रशिक्षक, कंसल्टेंट और अनुसंधानकर्ता के बतौर मिलते हैं।

घ). ई–गवर्नेंस

इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से आशय सरकार से नागरिकों (जी2सी), व्यवसायियों (जी2बी), कर्मचारियों (जी2ई) और सरकारों (जी2जी) को सरकारी सूचनायें और सेवायें देने के लिए नवीनतम संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ई–गवर्नेंस का विशिष्ट लाभ यह है कि नागरिकों को सरकारी सेवायें "कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय" उपलब्ध हो सके।

पाठ्यक्रम : समाज के अंतिम लोगों तक सरकारी सेवाओं को पहुँचाने में कई चुनौतियाँ हैं जिन पर नियंत्रण के लिये अनुसंधानकर्ताओं, पेशेवरों, एजेंसियों, प्रशिक्षकों की भारी जरूरत है जो इस पाठ्यक्रम को लागू करने के मूल में है।

संस्थान
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एन.आई. एस.जी.), हैदराबाद
- सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार
- भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान–केरल

अवसर : नेशनल इंस्टीटयूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्यरत है जो निजी और सरकारी क्षेत्रों में चालू परियोजनाओं के लिये समय–समय पर पेशेवरों के लिये रिक्तियों की घोषणा करता है. इसके अलावा निजी कंपनियों जैसे इन्क्रोमा ई–बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड भी इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाती है। इससे इतर अनुसंधान, परामर्श के क्षेत्र में भी अपार संभावनायें हैं.

ड). फोटोग्राफी

व्यक्ति के अंदर की सोच, कला को रचनात्मक बनाने का जरिया है कैमरा. इसके साथ यह आय का साधन भी है। सूचना–क्रांति के इस युग में संचार माध्यमों का महत्त्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है जिसमें कैमरे की भूमिका निर्विवाद रूप से विशिष्ट है।

पाठ्यक्रम : यूँ तो फोटोग्राफी में स्वयं ही अपनी क्षमताओं को निखारा जा सकता है, लेकिन फिर भी मन के विचारों को सही आकार, दिशा देने के लिये कुछ मूलभूत जानकारियों की जरूरत होती ही है. भारत के कुछ प्रतिष्ठित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इससे संबंधित पाठ्यक्रम कराये जाते हैं।

संस्थान
- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
- जामिया मिलिया इस्लामिया
- नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय
- सेंटर फॉर रिसर्च इन आर्ट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन
- फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, पुणे

अवसर : कई क्षेत्रों की तरह फोटोग्राफी में रोजगार की संभावनायें अत्यधिक हैं। इससे संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वयं को बतौर फोटो जर्नलिस्ट स्थापित किया जा सकता है। समाचारों से जुड़ी एजेंसियों को समाचारों को बेहतर तरीके से पाठकों तक पहुँचाने के लिये तस्वीरों की जरूरत पड़ती है। कम संवाददाताओं के होने के कारण वो लोगों से तस्वीरें लेते हैं जिसकी कीमत चुकायी जाती है. इसके अलावा फैशन अथवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्रापर के तौर पर भी स्वयं को स्थापित किया जा सकता है. विज्ञापनों की दुनिया में भी फोटोग्राफरों की महत्ता बहुत अधिक है. इसके अलावा शादियों, त्योहारों व विशेष आयोजनों पर फोटोग्राफी के जरिये अच्छी आमदनी की जा सकती है।

(संकलनकर्ता : मुकेश)

खतरे में डिजिटल डेमोक्रेसी

अमित चौहान

राजनीति को कीचड़ दलदल कहकर राजनीति से दूरी बनाने वाला युवा डिजिटल डेमोक्रेसी के चलते फिर से राजनीति में लौटा। लेकिन अब डिजिटल डेमोक्रेसी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये खतरा नेट न्यूट्रिलिटी का है– जिसे नेट की निरपेक्षता, समानता और नेट की आजादी भी कहा जाता है। यानि आजादी के साथ इंटरनेट पर दी जाने वाली हर उस सेवा का प्रयोग करना जिसका उपयोग आप करते आ रहे हैं।

लेकिन निजी टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं वे अब अपने यूजर्स के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में काम ना करते हुए विनियामक की भूमिका में काम करें। मतलब यह कि उनकी इंटरनेट सेवाओं का किस रूप में और इन साइटों को देखने का उपयोग किया जा रहा है यह वो तय करें। साथ ही कंपनियां इसके लिए ज्यादा कीमत भी वसूलना चाहती है। ये खतरा देखते हुए लाखों नेट यूजर्स ने इसका विरोध किया। नेट की आजादी की मांग कर रहे लाखों युवाओं ने इस संबंध विरोध दर्ज कराने के लिए ट्राई (टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को करीबन 10 लाख मेल भेजे। नेट की आजादी के पक्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी आवाज बुलंद की। परिषद ने नेट न्यूट्रिलिटी को लेकर ऑनलाइन पिटीशन का अभियान चलाया। जिसमें लाखों युवाओं ने ऑनलाइन याचिकाएं दायर की। ट्राई के मिले लाखों मेल और युवाओं की तीखी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए सरकार भी हरकत में आई। केंद्रीय दूर संचार मंत्रालय ने मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए जनवरी 2015 को दो समितियों का गठन किया। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार नेट यूजर्स, सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को है।

इंटरनेट की तटस्थता को बरकरार रखने के लिए

क्या है नेट न्यूट्रिलिटी

नेट न्यूट्रिलिटी को इंटरनेट निरपेक्षता या नेट समानता भी कहा जाता है मतलब आजादी के साथ इंटरनेट पर दी जाने वाली हर सेवा का प्रयोग करना जोकि अभीतक आप करते आए है। इसे ऐसे समझिए– जैसे आपके पास मोबाइल है और आप उसमें इंटरनेट का प्रयोग करते है। नेट का डाटा पैक लेने के लिए अभी आप टेलीकॉम कंपनियों को एक निश्चित शुल्क देते है और डाटा पैक रिचार्ज के बाद किसी भी साईट जैसे– गूगल, फेसबुक, ट्वीटर या व्हॉटस ऐप या अन्य साइटों पर जाने के लिए एक सी स्पीड होती है और आपको किसी भी साइट पर जाने के लिए अलग से डाटा पैक या पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन नेट निरपेक्षता लागू नहीं होती है तो टेलीकॉम कंपनियां टॉप साइटों और ऐप पर विजिट के लिए अलग से शुल्क वसूल सकती है। इसका सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ेगा।

संभवतः सरकारी कानून की जरूरत होगी। इस मामले में मजबूत तर्क ये दिया जा रहा है कि सरकार को मुक्त बाजार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा वाले मुक्त बाजार में जो सबसे कम कीमतों पर सबसे बेहतर सेवाएं देगा, फैसला उसी के पक्ष में आना चाहिए। हालांकि इस बात के खतरे भी है कि कंपनियां अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए गठजोड़ कर लें। खासकर उन बाजारों में जहां प्रतिस्पर्धा कम है। जैसे मोबाइल डाटा बाजार।

इस मामले ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स का तर्क है यह भी है कि उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा करने में हजारों करोड़ खर्च किए हैं जबकि व्हॉटस ऐप जैसी सेवाएं जो मुफ्त वाइस कॉल मैसेज सर्विस देकर उनके नेटवर्क का मुफ्त में फायदा उठा रही है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है।

इंटरनेट को तटस्थता से लागू नहीं किया गया तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ऑपरेटर्स इंटरनेट कालिंग सर्विस की एवज में डाटा की कीमतों के अलावा इसके लिए ज्यादा पैसे वसूल सकती है। या फिर इन सेवाओं के लिए अलग से डाटा की कीमतें तय की जा सकती है। टेलीकॉम कंपनियां कुछ सेवाओं को ब्लॉक कर सकती है ताकि यूजर्स के लिए इनका इस्तेमाल मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए व्हॉट्स ऐप की डाटा स्पीड को धीमा करके या इसे महंगा करके। फिलहाल नेट न्यूट्रिलिटी पर बहस जारी है।

ABVP ने भी चलाया अभियान

इंटरनेट की आजादी के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी अभियान चलाया। परिषद के कार्यकर्ताओं तथा युवाओं ने नेट निरपेक्षता के समर्थन में ऑनलाइन याचिकाएं दायर की। ■

सी-सैट क्वालीफाइंग पेपर बनने पर अभाविप का जश्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस परिसर में विजय जुलूस निकालकर यूपीएससी परीक्षा में सी-सैट को पात्रता परीक्षा बनाने पर जश्न मनाया। एबीवीपी के कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते हुए आर्ट्स फैकल्टी के गेट से क्रिस्चियन कॉलोनी तक गए जहां बड़ी संख्या में सिविल सेवा के अभ्यर्थी रहते हैं। उन्होंने उपनिवेशवादी मानसिकता और भारतीय भाषाओं के प्रति अन्याय के विरुद्ध नारे लगाये। उन्होंने विवेकानंद प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।

सिविल सेवा परीक्षा की प्रणाली, पाठ्यक्रम व अन्य विषयों पर डीओपीटी द्वारा कल एक विशेषज्ञ समिति की घोषणा की गयी है जिसका एबीवीपी ने हार्दिक स्वागत किया है। जब तक यह समिति अपने सुझाव नहीं दे देती तब तक सीसैट को क्वालीफाइंग बना दिया गया है। अतः उसमें सिर्फ पास होने की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष से हुए कई प्रदर्शनों व प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से सिविल सेवा के अभ्यर्थी व विद्यार्थी परिषद सी-सैट की परीक्षा को हटाने या उसे क्वालीफाइंग पेपर बनाने की मांग करते रहे हैं ताकि हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के तथा ग्रामीण पृठभूमि के विद्यार्थियों के साथ हो रहे अन्याय को रोक जा सके। किन्तु इस पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। कल सरकार द्वारा सीसैट को क्वालीफाइंग (पात्रता) पेपर बनाने पर एबीवीपी ने सरकार का धन्यवाद किया है। साथ ही यह भी मांग की है कि सिविल सेवा परीक्षा के अन्य स्तरों पर भी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हो रहे अन्याय को रोकना चाहिए।

निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ झारखंड में चक्का जाम

क्यों किया गया झारखंड बंद का आह्वान : इस साल नए सत्र में निजी स्कूलों ने री एडमिशन के नाम पर वार्षिक और विकास शुल्क में भारी वृद्धि की। परिषद सरकार और प्रशासन से एडमिशन के नाम पर वसूली जा रही फीस को बंद करने व सरकारी स्तर पर शुल्क निर्धारित करने, परीक्षा में एकरूपता लाने की मांग कर रहे थे। इसके विरोध में अभाविप ने पूरे प्रदेश में 21 अप्रैल को निजी स्कूल बंद कराने का आह्वान किया था। इसी योजना के तहत हजारीबाग में निजी स्कूलों को बंद कराने के लिये सैकड़ों कार्यकर्ता पहले होली स्कूल पहुंचे। वहां प्राचार्या ने वार्ता के बाद स्कूल बंद करने पर सहमति जताई। इसके बाद कार्यकर्ता संत जेवियर्स स्कूल पहुंचे। पुलिस ने चार लोगों को अंदर जाने दिया। बातचीत सकारात्मक नहीं होने पर कार्यकर्ता बाहर आए। इसी दौरान दो बसों से सैप के जवान पहुंचे और लाठियां बरसाने लगे। अफरा-तफरी में भी कई कार्यकर्ता अभिभावक चोटिल हो गए। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में प्रदेश सह मंत्री मनोज गुप्ता सहित अन्य शामिल थे।

शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज किये जाने के विरोध में प्रदेश के सभी समाहरणालयों में अभाविप कार्यकर्ताओं ने 23 अप्रैल को धरना दिया और 25 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया था। अभाविप कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में निजी विद्यालय प्रबंधन एडमिशन के नाम पर अभिभावकों व विद्यार्थियों का शोषण कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के बंद का असर राज्य के कई जिलों में दिखा। अभाविप कार्यकर्ता 25 अप्रैल को सुबह से ही सड़कों पर उतरे। उन्होंने वाहनों का परिचालन रोका और निजी स्कूलों के खिलाफ नारे लगाए। रांची, धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों में सुबह करीब तीन-चार घंटे तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। कई स्कूली बसों को जबरन लौटाया गया। रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा जिले में एनएच जाम करने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। चक्का जाम और प्रदर्शन के दौरान जिलों से सैकड़ों अभाविप कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, जिन्हें शाम तक रिहा कर दिया गया। 27 अप्रैल को अभिभावक संघ ने रांची बंद किया था।

कहां क्या हुआ : गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह समेत प्रांत के सभी जिलों में अभापिव कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। बोकारो, लोहरदग्गा में बंद का मिला जुला असर रहा। ■

प्रतिबंधित हो गौवध और गौमांस

रविशंकर

देश की कुछेक राज्य सरकारों ने बीफ यानि गौमांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर देश में कतिपय तथाकथित बुद्धिजीवियों का प्रलाप जारी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में अभी तक यही बात स्थापित नहीं की जा सकी है कि गौमांस आस्था के साथ–साथ आर्थिक प्रश्न भी है। देश की कृषि व्यवस्था हजारों वर्षों से गौआधारित रही है। गौआधारित होने के कारण ही वह इतने वर्षों से चली आ रही है। अन्यथा हरित क्रांति के मात्र 40 वर्षों में न केवल भूमि बंजर होने लगी है, बल्कि उत्पादन भी घटने लगा है। कुल मिला कर कृषि घाटे का सौदा बन गई है और किसान आत्महत्या करने को विवश हो गया है। इसलिए गौमांस पर प्रतिबंध और साथ ही मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। मांस उत्पादन और गौमांस के व्यापार में देश को लाभ की बजाय हानि ही अधिक है। कुछेक बिंदु यहां प्रस्तुत हैं।

● मांस उत्पादन में पर्यावरण का भारी नुकसान है। मांस के उत्पादन में सबसे अधिक पानी की खपत होती है। इसका अर्थ है कि आप केवल मांस का निर्यात नहीं कर रहे होते हैं, मांस के रूप में आप देश का बेशकीमती पानी भी निर्यात कर रहे होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न भोज्य पदार्थों के निर्माण में लगने वाले पानी की मात्रा इस प्रकार है –

एक किलो बीफ के निर्माण में करीब 15400 लीटर पानी लगता है, परंतु अगर आलू उपजाना हो तो इतने ही पानी में करीब 50 किलो आलू उपजा सकते हैं। एक गाय को अपने जीवन काल में करीब बीस लाख लीटर पानी की जरूरत होती है, ऐसे में सोचा जा सकता है कि जब बैलों–सांडों को बीफ बनाने के लिए पाल–पोस रहे हों तो हिसाब लगा लीजिये कि पानी की दृष्टि से कितना खतरनाक रूप से खर्चीला है यह। इससे यह साफ है कि मांस का निर्यात देश के जल संसाधन के लिए काफी नुकसानदेह है।

मांस	पानी (ली.)
बीफ	15400
मटन	6400
चिकन	4300
चावल	1400
आलू	290

● पशु देश का राष्ट्रीय धन है। इनके पालन पोषण पर देश का संसाधन खर्च होता है। उदाहरण के लिए एक बकरे को मात्र कुछ सौ रुपए में विदेश में बेचा जाता है जबकि उस एक बकरे को पालने और भेजने में देश का 60,000 रुपया खर्च होता है। इसी प्रकार सभी पशुओं की बात है। एक किलो मांस बनाने के लिए सैकड़ों टन पानी, सैकड़ों किलो अनाज आदि खर्च होता है। इसलिए मांस के निर्यात से परोक्ष रूप से देश के संसाधनों का भारी शोषण होता है।

● इंसानी सेहत पर गाय के गोबर की खाद का असर 1920 के जमाने में अमेरिका के मिसूरी यूनिवर्सिटी के मृदा वैज्ञानिक प्रोफेसर विलियम एलब्रेक्ट ने अपनी मशहूर किताबों "न्यूट्रीशन एंड फिजिकल डिजेनेरेशन" और "सोइल फर्टिलिटी एंड एनिमल हेल्थ" में दुनिया को यह समझाया कि स्वस्थ जमीन में ही स्वस्थ खेती होती है। स्वस्थ खेत की फसल से ही ऐसा अनाज मिलता है जिसे खाने से इंसान स्वस्थ रहा सकता है और इंसान की नसल भी खराब होने से बचती है। स्वस्थ जमीन के चारे व घास पर पली गाय ही स्वस्थ होती है। और आखिरी बात गाय के गोबर, मूत्र से ही जमीन की तंदुरुस्ती बनी रहती है। इस तरह गाय के दूध से गाय का गोबर ज्यादा कीमती है क्योंकि वह जमीन को ठीक रख कर सब को ठीक अनाज देने देती है। देश में जितनी ज्यादा गायें होंगी, उतना गाय के गोबर से जमीन का ज़्यादा सुधार हो सकेगा। रासायनिक खाद से जो देश को एक लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी जाती है, बच सकती है। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से फसल में कीड़े लगने को रोकने के लिए पेस्टीसाइड और इंसेक्टीसाइड के इस्तेमाल से जमीन की उत्पादकता और इंसानी सेहत लगातार खराब होती जा रही है।

● गाय की पर्यावरणीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण

भूमिका है। 1950 के दशक के बाद अफ्रीका के वन संरक्षण अनुसंधान से यह सिद्ध हो चुका है कि जिन जंगलों की हरियाली खतम हो गई थी और जहां की जमीन बंजर होती जा रही थी, वहां बंजर जमीन पर गाय को छोड़ने से हरियाली वापस आ गई। गाय के गोबर व गोमूत्र से जमीन में बारिश के पानी को रोकने क्षमता बढ़ गई और बारिश का पानी बह कर नहीं जाने से बंजर जमीन दोबारा हरी भरी हो गई। आज सारे दुनिया में इंगलेंड के एलेन सेवोरी इंस्टीट्यूट द्वारा गाय को जंगल में छोड़ने से गाय के गोबर व गोमूत्र से बंजर जमीन दोबारा हरा भरा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पर्यावरण के कार्बन और नाइट्रोजन चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए गाय एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती है। ऐसे में मांस के लिए उसकी हत्या से पर्यावरण का चक्र बिगड़ेगा।

- मांस निर्यात से देश में पशुओं की तस्करी बढ़ रही है। आम तौर पर उतने पशु उपलब्ध ही नहीं हैं, जिनका मांस बाहर निर्यात किया जा सके। ऐसे में, स्वस्थ व युवा पशुओं की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। निर्यात बंद होने से इस तस्करी पर रोक लगेगी। मांस निर्यात से आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। तस्करी और आतंकवाद दोनों ही अपराधों पर रोक के लिए मांस निर्यात पर प्रतिबंध आवश्यक है।

- मांस निर्यात के लिए की जाने वाली पशुओं की चोरी और तस्करी से देश में कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और समाज की शांति भी भंग होती है।

- पशुओं को काटे जाते समय उनके क्रंदन से उठने वाली आवाज की तरंगों से भूकम्प का खतरा भी बढ़ता है। इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध किए गए हैं जो बताते हैं कि पशुओं के आर्तनाद से भूकम्प पैदा करने वाली तरगें निकलती हैं।

- यह दुर्भाग्यजनक है कि मांस निर्यातक देश के कानूनों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वर्तमान में एपीडा ने केवल 29 कत्लखानों को मांस निर्यात का लाइसेंस दिया है। परंतु मांस निर्यात करने के लिए एफएसएसआई (FSSI) प्रमाणपत्र का होना भी आवश्यक है जो इनमें से किसी भी कत्लखाने के पास नहीं है। बिना एफएसएसआई प्रमाणपत्र के मांस के निर्यात करने पर प्रतिदिन पांच लाख रूपये का जुर्माना भी है।

इस प्रकार देखा जाए तो मांस का निर्यात हर दृष्टि से देश के लिए घाटे का ही सौदा है। दुनिया में गाय से गरीबी उन्मूलन के प्रयोग हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इस पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था गाय के दूध पर चलती है। अमेरिका में गोबर की खाद कई सौ रूपये प्रति किलो की दर से बिकती है लेकिन गौपालक देश भारत में गौमांस के लिए बहस की जा रही है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। ■

गरीबों का भोजन गौमांस या नमक-रोटी ?

अपने देश के गरीबों का सामान्य भोजन क्या है? अभी तक तो नमक–रोटी को ही गरीबों का भोजन समझा जाता रहा है। बहुत हुआ तो चना–चबैना को भी जोड़ लिया जाता है। परंतु देश की राजधानी में रहने वाले सेकुलर अंग्रेजी मीडिया के झंडाबरदारों के लिए गरीबों का भोजन गौमांस है। कुछ वर्ष पहले विश्वमंगल गौ–ग्राम यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर यात्रा के आयोजकों से बातचीत में एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र की पत्रकार ने पूछा कि गौहत्या बंद हो जाने से गरीब लोगों को भोजन का संकट नहीं हो जाएगा क्या?

यह सवाल बड़ा ही चौंकाने वाला था। आज तक किसी भी समझदार अर्थशास्त्री ने ऐसा गंभीर सवाल नहीं उठाया है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत का एक उपक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने तो गाय से अन्त्योदय पर एक पैनल बना रखा है। यानी वह गाय द्वारा गरीबों की गरीबी दूर करना चाहती है। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन भी विशेष रूप से जोर देने में जुटी हुई है। फिर गाय को बचाने से गरीबों को भोजन का संकट हो जाएगा, इस सोच और मानसिकता को क्या कहा जाए?

25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए भूकंप के तबाही की कुछ तस्वीरें तथा 'प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद' द्वारा चलाया जा रहे राहत कार्य में उत्तरांचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगतसिंह कोशियारी

RNI No. 32464/78

गुरुदेवाय नमः

राज्य स्तरीय अभिप्रेरणा महोत्सव

दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी
9 मई, 2015 को
प्रख्यात चिंतक एवं विचारक
श्री सुरेश जी सोनी
का व्याख्यान

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

उद्देश्य :

- भारतीयता का भाव-जागरण
- समर्थ नागरिक निर्माण
- भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अवगाहन
- व्यक्तित्व निर्माण एवं अनवरत संवर्धन
- भारतीय नैतिक मूल्यों का परिपालन एवं सृजन

श्री उमाशंकर गुप्ता
मंत्री, उच्च, तकनीकी शिक्षा
एवं कौशल विकास

समय : प्रातः 10.30 बजे
कार्यक्रम स्थल :
संत हिरदाराम आडिटोरियम गर्ल्स डिग्री
कॉलेज कैम्पस, लेक रोड, हिरदाराम नगर
(बैरागढ़) भोपाल

श्री दीपक जोशी
राज्यमंत्री, उच्च एवं स्कूल शिक्षा

आप सादर आमंत्रित हैं

व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन